

an>

Title: Need to allocate funds for Rural Drinking water scheme.

**श्री पी.पी.चौधरी (पत्नी) :** माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि अति सूखा क्षेत्र होने के बावजूद राजस्थान राज्य में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए भारत सरकार से ग्रामीण पेयजल के लिए प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता में अत्यधिक कटौती की गयी है। पूर्व के वर्षों में मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत पेयजल योजनाओं की इस वर्ष 5842 करोड़ रुपये की देनदारियां बकाया हैं। ये सभी देनदारियां भारत सरकार के दिशानिर्देशों के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। इस वर्ष के लिए पेश किए गए बजट के अनुसार राजस्थान राज्य को ग्रामीण पेयजल योजना अंतर्गत केवल 300 करोड़ रुपये प्राप्त होना प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले सीधे-सीधे 1000 करोड़ रुपये कम है। गत वर्ष इस मद में भारत सरकार से राजस्थान राज्य को 1304 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

अतः मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में पुनर्विचार करके ग्रामीण पेयजल योजना में इस वर्ष कम से कम 5842 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने चाहिए ताकि पिछली देनदारियों को चुका कर राजस्थान राज्य में पेयजल योजना सुचारू रूप से चलाई जा सके।

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Gajendra Singh Shekhawat is allowed to associate with the issue raised by Shri P.P.Chaudhary.